मेसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और अन्य

बनाम

छोटा बिरसा उरांव।

सिविल अपील संख्या.4890/2014

मार्च 25, 2014

**ज्ञान सुधा मिश्रा एवं**

**पिनाकी चंद्र घोस, न्यायमूर्ति**

*सेवा कानून:*

*जन्म तिथि-का सुधार - कर्मचारी का अपनी जन्म तिथि को सही करने और अपने सेवा रिकॉर्ड में विसंगतियों को सुधारने का दावा-नियोक्ता द्वारा अस्वीकार-उच्च न्यायालय द्वारा अनुमत-माना गया : दिनांक परिवर्तन के कारण होने वाली असुविधाओं को रोकने के उद्देश्य से, एक अन्यायपूर्ण कर्मचारी को उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, विशेष रूप से जब उसने निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया हो और इन-हाउस तंत्र-सार्वजनिक निगमों का सहारा लेकर मुकदमेबाजी से बचने का प्रयास किया हो! विभागों को अपने स्वयं के कर्तव्य को छोड़ने से लाभ नहीं होना चाहिए-तत्काल मामले में, अपीलार्थी-कंपनी कार्यान्वयन निर्देश में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने में विफल रही-यह विसंगतियों के कारण था जो कि अपीलार्थी ने अपने सभी कर्मचारियों को इसे सुधारने का मौका दिया - उत्तरदाता ने उपलब्ध प्रक्रिया का विधिवत पालन किया - अपीलार्थी अपने कार्यों से बाध्य हैं और तकनीकी आधार पर प्रत्यर्थी के दावे को अस्वीकार करने का उनका प्रयास गलत है-यह उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा सही ढंग से निर्धारित किया गया है कि विवाद सेवा के अंतिम चरण में या सेवानिवृत्ति की पूर्व संध्या पर नहीं उठाया गया था, बल्कि इसे जल्द से जल्द उठाया गया था - उच्च न्यायालय का आदेश किसी भी हस्तक्षेप का आह्वान नहीं करता है|*

*साक्ष्य:*

*जन्मतिथि-स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र-का प्रमाणिक मूल्य - स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में प्रासंगिक तिथि-आयोजितः कार्यान्वयन निर्देश संख्या 76.8 खंड (i) (क) स्कूल*

*छोड़ने के प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्मतिथि को सही मानकर जन्मतिथि में संशोधन की अनुमति देता है बशर्ते कि ऐसे प्रमाण पत्र शैक्षणिक संस्थान द्वारा रोजगार की तारीख से पहले जारी किए गए हों-प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख वास्तव में स्कूल में प्रासंगिक रिकॉर्ड के साथ उस तारीख को संदर्भित करने का इरादा रखती है जिसके आधार पर प्रमाण पत्र जारी किया गया है-एक स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र आमतौर पर छात्र द्वारा स्कूल छोड़ने के समय जारी किया जाता है, बाद में इसकी एक प्रति भी प्राप्त की जा सकती है जहां एक छात्र अपने उक्त स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र को भूला देता है और इसकी एक नई प्रति के लिए आवेदन करता है-नई प्रति जारी करने से प्रासंगिक रिकॉर्ड में बदलाव नहीं हो सकता है जो स्कूल के रिकॉर्ड में प्रवेश की तारीख और छात्र की जन्म तिथि से स्कूल के रिकॉर्ड में प्रचलित है, जो स्कूल के रिकॉर्ड में विधिवत दर्ज है।*

**प्रत्यर्थी, अपीलार्थी नं. 1 कंपनी में 31.3.1973 को कार्यान्वित हुआ था । उस समय उनकी जन्मतिथि 15.2.1947 दर्ज की गई थी। उन्होंने 1979 में माध्यमिक विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जिसमें उनकी जन्म तिथि 6.2.1950 दर्ज की गई थी। 1986 में प्रत्यर्थी ने खनन सरदारशिप पास की और उसी को स्वीकार करते हुए प्रमाण पत्र में उसकी जन्म तिथि 6.2.1950 दर्ज की गई। 1987 में कार्यान्वयन निर्देश संख्या 76 के संदर्भ में विसंगतियों की पहचान करने और सेवा रिकॉर्ड को सही करने की प्रक्रिया में, प्रतिवादी ने विशेष रूप से मांग की कि गलत जन्म तिथि को ठीक किया जाए जैसा कि खनन सरदार प्रमाणपत्र और स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र में उल्लेख किया गया है। हालांकि इसका कोई असर नहीं हुआ। बाद में प्रत्यर्थी ने अपनी जन्मतिथि के सुधार के लिए 16.7.2006 को अभ्यावेदन किया, लेकिन उसे 19.7.2006 को अस्वीकार कर दिया गया। दिनांक 2.8.2006 के आदेश द्वारा, प्रत्यर्थी को सूचित किया गया था कि उसे 28.2.2007 से सेवानिवृत्त होना था। प्रत्यर्थी ने इस आधार पर उक्त आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए एक रिट याचिका दायर की कि उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख की गणना गलत जन्म तिथि पर भरोसा करके गलत तरीके से की गई थी, जिसे खनन सरदार प्रमाणपत्र और स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र में दिए गए अनुसार ठीक किया जाना चाहिए था। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया। कंपनी द्वारा दायर लेटर्स पेटेंट अपील को खारिज कर दिया गया।**

**अपील को खारिज करते हुए, अदालत ने कहाः 1.1 जन्म तिथि में परिवर्तन के कारण होने वाली असुविधाओं को रोकने के उद्देश्य से, एक अन्यायपूर्ण कर्मचारी को उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, विशेष रूप से जब उसने निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया हो और आंतरिक तंत्र का सहारा लेकर मुकदमेबाजी से बचने का प्रयास किया हो। सार्वजनिक निगमों/विभागों, डी को अपने स्वयं के कर्तव्य की चूक से लाभ नहीं होना चाहिए। तत्काल मामले में, अपीलार्थी-कंपनी कार्यान्वयन निर्देश में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने में विफल रही। यह अपीलार्थी की चूक है और प्रत्यर्थी की निष्क्रियता नहीं है जिसके कारण न्यायालयों में विवाद को विलंबित स्तर पर**

उठाया गया। ऐसे निगमों का रवैया, जिसमें जन्म तिथि के सुधार से बचने के लिए, मुकदमेबाजी को अनावश्यक रूप से केवल इसलिए बढ़ाया जाता है क्योंकि उनके पास कई संसाधन हैं, बड़े पैमाने पर समाज के प्रति समानता और कर्तव्य के खिलाफ जाता है।
[पैरा 13] [905-डी-एफ]

1.2 1973 में प्रत्यर्थी सेवा में नियुक्त हुआ और फॉर्म 'बी' रजिस्टर भरा गया और जब इसे 1983 में एक बार पुनः भरा गया, तो स्थायी पते, पिता के नाम और नियुक्त होने की तारीख के संबंध में कुछ विसंगतियां थीं। 1987 में, जब अपीलार्थी कार्यान्वयन निर्देश सं. 76 राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौते में निहित, सेवा अभिलेखों के सत्यापन के लिए सभी कर्मचारियों का विवरण उपलब्ध कराया गया और उन्हें अपने सेवा अभिलेखों में विसंगतियों की पहचान करने और उन्हें सुधारने का मौका दिया गया, प्रत्यर्थी ने अपनी नियुक्ति की तारीख, पिता का नाम, स्थायी पता और जन्म तिथि के बारे में गलत विवरण के रूप में विवाद उठाया। प्रत्यर्थी ने उपलब्ध प्रक्रिया का विधिवत पालन किया। ऐसी परिस्थितियों में, अपीलार्थी अपने कार्यों से बाध्य था, और तकनीकी आधार पर प्रत्यर्थी के दावे को अस्वीकार करने का उसका प्रयास गलत था। अपीलार्थियों को कार्यान्वयन निर्देश संख्या द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था। 76 किसी मौजूदा कर्मचारी की जन्मतिथि निर्धारित करना। इस प्रकार, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा यह स्पष्ट और सही रूप से निर्धारित किया गया है कि विवाद सेवा के अंतिम चरण में या सेवानिवृत्ति की पूर्व संध्या पर नहीं उठाया गया था, बल्कि इसे 1987 में जल्द से जल्द संभव अवसर पर उठाया गया था जब प्रतिवादी को विसंगति का पता चला था।
[पैरा 8,11-12] [899-सी-एफ, 902-ई-एफ; 903 -ए-बी, डी-ई]

1.3 उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी कंपनी के विधिक निरीक्षक द्वारा दाखिल किए गए पूरक शपथपत्र के आधार पर, यह स्वीकार करते हुए कि विद्यालय छोड़ने का प्रमाण-पत्र सत्यापित किया गया था और वास्तविक पाया गया था, विद्यालय छोड़ने के प्रमाण-पत्र की प्रामाणिकता का विधिवत सत्यापन किया। इसके अलावा, कार्यान्वयन निर्देश संख्या 76 खंड (i) (ए) स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि को सही मानते हुए जन्म तिथि के सुधार की अनुमति देता है, बशर्ते कि ऐसे प्रमाण पत्र शैक्षणिक संस्थान द्वारा रोजगार की तारीख से पहले जारी किए गए हों। प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख वास्तव में उस स्कूल में प्रासंगिक रिकॉर्ड के साथ उस तारीख को संदर्भित करने का इरादा रखती है जिसके आधार पर प्रमाण पत्र जारी किया गया है। एक स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र आमतौर पर छात्र द्वारा स्कूल छोड़ने के समय जारी किया जाता है, बाद में इसकी एक प्रति भी प्राप्त की जा सकती है जहां एक छात्र अपने उक्त स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र को गलत स्थान पर रखता है और इसकी एक नई प्रति के लिए आवेदन करता है। नई प्रति जारी करने से उस प्रासंगिक अभिलेख में परिवर्तन नहीं हो सकता है जो विद्यालय के

**अभिलेखों में विधिवत दर्ज छात्र के प्रवेश की तिथि और जन्म तिथि से विद्यालय के अभिलेखों में प्रचलित है। इसलिए, उच्च न्यायालय के आदेश में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। [पैरा 14-15] (905-एच; 906-ए-सी, डी-जी)**

जी. एम. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, पश्चिम बंगाल बनाम शिब कुमार दुशाद और अन्य **2000 (4) अनुपूरक SCR 336 = (2000) 8 SCC 696**; भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बनाम पीठासीन अधिकारी और अन्य (**1995) पूरक 2 एस. सी. सी. 598**; पंजाब राज्य बनाम एस. सी. चड्ढा **2004 (2) एससीआर 216 = (2004) 3 एससीसी 394**; यूपी राज्य एवं अन्य बनाम शिव नारायण उपाध्याय **2005 (1) अनुपूरक एससीआर 847 = (2005) 6 एस. सी. सी. 49**; महाराष्ट्र राज्य और अन्य बनाम गोरकनाथ सी सीताराम कांबले और अन्य **2006 (3) पूरक एससीआर 685 = (2010) 14 एससीसी 423**; रजिस्ट्रार जनरल, मद्रास उच्च न्यायालय बनाम एम. माणिकम और अन्य **(2011) 9 एस. सी. सी. 425**; आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय बनाम एन. संन्यासी राव **2011 (13) एससीआर 403 = (2012) 1 एससीसी 674**; और मोहम्मद यूनुस खान बनाम यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड **2008 (14) एससीआर 1114 = (2009) 1 अनुभाग 80- उद्धृत।**

केस लॉ सन्दर्भ

**2000 (4) पूरक एस. सी. आर. 336 उद्धृत पैरा 4**
**(1995) पूरक। 2 धारा 598 उद्धृत पैरा 4**
**2004 (2) एस. सी. आर. 216 उद्धृत पैरा 9**
**2005 (1) पूरक एस. सी. आर. 847 उद्धृत पैरा 9**
**2006 (3) पूरक एस. सी. आर. 685 उद्धृत पैरा 9**
**(2011) 9 धारा 425 उद्धृत पैरा 9**
**2011 (13) एस. सी. आर. 403 उद्धृत पैरा 10**
**2008 (14) एस. सी. आर. 1114 उद्धृत पैरा 10**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 2014 का 4890।

2010 का एल.पी.ए. संख्या 90 में रांची में झारखंड उच्च न्यायालय की न्यायपालिका के दिनांक 20.09.2010 के निर्णय और आदेश से।

अनुपम लाल दास, अनिरुद्ध सिंह, दीदेश सिन्हा अपीलार्थियों की ओर से।
गोपाल प्रसाद प्रतिवादी के लिए ।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

**<u>पिनाकी चंद्र घोष, जस्टिस.</u>**

**1.** अनुमति प्रदत्त की गई|

**2.** वर्तमान अपील दिनांक 20 सितंबर, 2010 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 90 में रांची में झारखंड के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उत्पन्न होती है, जो विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा एक रिट W.P. (स) 2007 का 496 में पारित 11 दिसंबर, 2009 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। वर्तमान मामले में प्रत्यर्थी द्वारा दायर ,जिसमें न्यायालय ने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के क्षेत्र के परियोजना अधिकारी, जामुनिया ओपन कास्ट परियोजना (जिसे इसके बाद 'परियोजना अधिकारी' के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा पारित 2 अगस्त, 2006 के आदेश को रद्द कर दिया। जिसमें कहा गया है कि प्रत्यर्थी 28 फरवरी, 2007 को सेवानिवृत्त होगा|

**3.** इसके लिए संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैंः

प्रत्यर्थीअपीलकर्ता संख्या 1 भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल), कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के तहत एक सरकारी कंपनी, में शामिल हुआ , विवादित आदेश के अनुसार उनके शामिल होने की तारीख 31 मार्च, 1973 बताई गई है।

ज्वाइन करने के समय , फॉर्म बी में उनकी जन्म तिथि 15 फरवरी, 1947 के रूप में दर्ज की गई थी, जो खान नियम, 1955 के तहत निर्धारित एक वैधानिक फॉर्म है, उसी को दर्ज करने का आधार स्पष्ट नहीं है| प्रत्यर्थीने 12 अक्टूबर, 1979 को माध्यमिक विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया, जिसमें वर्णित था कि उसने जनवरी 1964 से अगस्त 1964 तक धनबाद के एक सरकारी स्कूल, राज्य संपूर्ण उन्नत विद्यालय, बाघमारा में पढ़ाई की। उक्त प्रमाणपत्र में, उत्तरदाता की जन्म तिथि 6 फरवरी 1950 दर्ज की गई है, जो उपरोक्त फॉर्म बी होने के कारण सेवा रिकॉर्ड में दर्ज की गई उनकी जन्म तिथि के विरोधाभासी है।

**3.2.** इसके बाद , 1983 में, उन्हें जामुनिया ओपन कास्ट प्रोजेक्ट में स्थानांतरित कर दिया गया और जैसा कि कहा गया है, उन्होंने एक बार फिर फॉर्म बी पर हस्ताक्षर किए, जिसमें उनकी जन्म तिथि 15 फरवरी, 1947 दर्ज की गई थी और उन्होंने कथित तौर पर तब कोई आपत्ति नहीं उठाई थी।

**3.3.** 1986 में, उत्तरदाता ने माइनिंग सरदारशिप पास की और उसी को स्वीकार करते हुए प्रमाण पत्र में उनकी जन्म तिथि 6 फरवरी, 1950 के रूप में दर्ज की गई थी, जो उपरोक्त स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र में दर्ज की गई तारीख के अनुरूप थी। इसलिए, उत्तरदाता के विवरण के रिकॉर्ड के दो सेट मौजूद थे; सबसे पहले एक तरफ फॉर्म बी रजिस्टर है जिसमें जन्म तिथि 15 फरवरी 1947 दर्ज की गई थी, और दूसरा माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट और स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट है जिसमें जन्म तिथि 6 फरवरी

1950 दर्ज की गई थी|

1987 में, राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता III (इसके बाद एनसीडब्ल्यूए III के रूप में संदर्भित) को लागू करने के पश्चात कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड को स्पष्ट करने के लिए निर्देश दिए गए थे। कार्यान्वयन निर्देश संख्या 76 के अनुसार, अपीलार्थी नं. 1 ने अपने कर्मचारियों को कार्यान्वयन निर्देशों द्वारा निर्धारित नॉमिनी फॉर्म प्रदान किए, जिसमें फॉर्म बी रजिस्टर में सेवा रिकॉर्ड से प्रासंगिक उद्धरण शामिल थे, इस तरह कर्मचारियों को रिकॉर्ड में किसी भी विसंगति या त्रुटि की पहचान करने और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उसे ठीक करने में सक्षम बनाता है। इसके बाद प्रत्यर्थीको अपनी जन्म तिथि के संबंध में रिकॉर्ड में विसंगतियों के बारे में पता चल गया, नियुक्ति की तारीख, पिता का नाम और स्थायी पता; इसमें उत्तरदाता ने परियोजना अधिकारी को अभ्यावेदन दिया, उपरोक्त त्रुटियों को सुधारने के लिए जामुनिया ओपन कास्ट प्रोजेक्ट और उन्होंने विशेष रूप से खनन सरदार प्रमाणपत्र और स्कूल छोड़ने के प्रमाणपत्र में उल्लिखित तारीख के अनुसार गलत जन्म तिथि को ठीक करने की मांग की। ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित अधिकारियों ने पिता के नाम और स्थायी पते के संबंध में विसंगतियों को ठीक किया; हालांकि जन्म तिथि और नियुक्ति की तारीख अपरिवर्तित रही| इसके बाद, जैसा कि उत्तरदाता द्वारा कहा गया है, बाद में उन्होंने 16 जुलाई को संबंधित परियोजना अधिकारी को प्रतिनिधित्व किया, माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट के अनुसार फॉर्म बी रजिस्टर में जन्म तिथि में सुधार के लिए 2006 और इसे अपीलकर्ता कंपनी द्वारा 19 जुलाई 2006 के पत्र

के माध्यम से अस्वीकार कर दिया गया था|

परियोजना अधिकारी ने 2 अगस्त, 2006 के आदेश के माध्यम से प्रत्यर्थीको सूचित किया कि वह 28 फरवरी, 2007 से सेवानिवृत्त होने वाला है। इससे व्यथित होकर, प्रत्यर्थीने डब्ल्यू. पी. (एस) नंबर 2007 का 496 रिट दायर की। इस आधार पर परियोजना अधिकारी द्वारा सेवानिवृत्ति के आदेश को रद्द करने के लिए कि सेवानिवृत्ति की तारीख को गलत जन्म तिथि पर भरोसा करके गलत तरीके से गणना की गई है जिसे एनसीडब्ल्यूए III के अनुसार सुधारा जाना चाहिए था, जिसमें यह प्रावधान था कि माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट और स्कूल छोड़ने के सर्टिफिकेट को एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉई की जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में प्रामाणिक दस्तावेजों के रूप में माना जाना चाहिए। अपीलकर्ता कंपनी ने बिना चुनौती दिये उक्त की वास्तविकता पर प्रत्यर्थीने फॉर्म 'बी' रजिस्टर जन्मतिथि का निर्णायक प्रमाण है इस आधार पर प्रतिवाद किया, जन्म तिथि के रूप में यह प्रत्यर्थी होने के नाते कर्मचारी के हस्ताक्षर द्वारा सत्यापित किया गया था; और तब प्रविष्टि स्वीकार करने के बाद, प्रत्यर्थी बीस वर्षों के बाद और अपनी सेवा के अंतिम चरण में किसी भी विवाद को उठाने का हकदार नहीं है। उच्च न्यायालय ने रिट की अनुमति देते हुए निर्धारित किया कि प्रत्यर्थीने अपने करियर के अंतिम अंत में इस तरह का दावा नहीं किया था, बल्कि इस तरह का दावा 1987 में ही किया गया था और अपीलकर्ता कंपनी प्रत्यर्थीद्वारा उठाए गए विवाद का उचित जवाब देने में विफल रही थी। इसके द्वारा, अदालत ने अपीलकर्ता कंपनी को उत्तरदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणपत्रों के आधार पर जांच करने और आदेश पारित होने के तीन महीने के भीतर सौंपे गए कारणों के साथ लिए गए

निर्णय को उत्तरदाता को प्रभावी ढंग से सूचित करने का निर्देश दिया।

नाराज, अपीलकर्ता कंपनी ने एक लेटर पेटेंट अपील को प्राथमिकता दी, वह आदेश जिसमें यहां आक्षेप किया गया है। उच्च न्यायालय ने कार्यान्वयन निर्देश संख्या 76 की धाराओं पर विचार करते हुए अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हुए अपील को खारिज कर दिया।

**3.6.** इसके बाद, मामला हमारे सामने है।

**4.** वर्तमान अपील में अपीलार्थी हमारे सामने आया है कि विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया जाए। अपीलार्थी का मामला, सबसे पहले, जब विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र कार्यान्वयन निर्देश सं. 76, उच्च न्यायालय ने उक्त निर्देश में दिए गए दस्तावेजों के साथ इसे प्रतिस्थापित करने में गलत था, जिससे एक ऐसी स्थिति पैदा हुई जो फॉर्म 'बी' रजिस्टर जैसे अन्य सभी वैधानिक दस्तावेजों का स्थान ले लेती है। दूसरा, उच्च न्यायालय को यह मानना चाहिए था कि फॉर्म बी रजिस्टर में दर्ज जन्म तिथि खान अधिनियम के तहत एक सांविधिक दस्तावेज होने के नाते बाध्यकारी है और इससे पहले एक गैर-सांविधिक दस्तावेज नहीं हो सकता है और इसलिए, *उच्च न्यायालय की अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित करना कि स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र और खनन सरदार प्रमाणपत्र कंपनी के अभिलेखों और अन्य वैधानिक दस्तावेजों पर वरीयता लेंगे, G.M. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, पश्चिम बंगाल बनाम शिब कुमार दुशाद और अन्य में इस न्यायालय के निर्णय के विपरीत है।* "" "तीसरा, अपीलार्थी ने अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा अधिकारिता के प्रयोग को यह मानते हुए चुनौती

दी है कि कर्मकार के रूप में प्रत्यर्थी औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन फोरम से प्रभावी उपाय 1 (2000) 8 एससीसी 696 का लाभ उठा सकता है और प्रत्यर्थी अपने कार्यकाल के अंतिम समय में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बनाम पीठासीन अधिकारी और एएनआर2 में इस प्रकार का विवाद उठा सकता है"

" . चौथा, प्रत्यर्थी ने स्कूल छोड़ने के प्रमाणपत्र और खनन सरदार प्रमाणपत्र पर भरोसा किया है, जो वर्तमान कर्मचारियों के लिए जन्म तिथि के निर्धारण की समीक्षा के लिए कार्यान्वयन निर्देश संख्या 76 में निर्दिष्ट नहीं हैं। । चुनौती दिए गए आदेश को लागू करने से विवेकहीन कर्मचारी ऐसे दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं और उनका शोषण कर सकते हैं। पांचवां, प्रत्यर्थी ने नियुक्ति के समय फॉर्म 'बी' रजिस्टर पर हस्ताक्षर करते समय अपनी जन्मतिथि 1 जनवरी, 1973 को शामिल होने पर 15 फरवरी, 1947 के रूप में सत्यापित की थी और बाद में 1983 में उनके स्थानांतरण पर; चूंकि वह एक पर्यवेक्षी कर्मचारी है, अंग्रेजी पढ़ने और लिखने और समझने में सक्षम है , इसलिए उनका सत्यापन स्वीकार करने के बराबर है और चौदह साल बाद 1987 में उनका विवाद उठाना गलत है।। छठा, अपीलार्थी ने द्वारा स्कूल छोड़ने के प्रमाणपत्र पर रखी गई निर्भरता को चुनौती दी है कि यह उनकी नियुक्ति के छह साल बाद 12 अक्टूबर, 1979 को जारी किया गया था और चूंकि खनन सरदार प्रमाणपत्र उसी निर्भरता पर आधारित था, इसलिए यह भी संदिग्ध है; इसके अलावा, चूंकि दोनों दस्तावेज़ रोजगार की तारीख के बाद जारी किए गए थे, इसलिए वे जन्म तिथि में सुधार का आधार नहीं बना सकते हैं; इसके अलावा, अपीलार्थी ने स्कूल छोड़ने के

प्रमाणपत्र की यथार्थता को इस आधार पर चुनौती दी है कि कथित प्रमाणपत्र को जिला शिक्षा आयुक्त द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था; कि प्रासंगिक अवधि के लिए जब प्रत्यर्थीकथित रूप से स्कूल गया था, उपस्थिति रजिस्टर उपलब्ध नहीं था और सत्यापन श्री बिरसा प्रसाद उरांव के संबंध में था; यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि ये विसंगतियां जो कंपनी के कानूनी निरीक्षक (जिन्हें विधिवत आरोप-पत्र दायर किया गया था) द्वारा कवर की गई थीं उत्तरदाता के साथ मिलकर स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र को संदिग्ध बनाएं। अंत में, अंत में, यह तर्क दिया गया कि प्रत्यर्थीने नियुक्ति के तीस साल बाद एक विलंबित रिट दायर करके इस मुद्दे को बहुत देर से उठाया और बीस वर्षों तक ज्ञान का दावा किया|

**5.** इसके विपरीत, प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी के दावों का खंडन किया है और प्रस्तुत किया है कि उसने अपनी सेवा के अंतिम अंत में अपनी जन्म तिथि पर विवाद नहीं किया है जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पाया गया है यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्यर्थी31 मार्च 1973 को सेवा में शामिल हुआ, जब उनकी जन्म तिथि 15 फरवरी 1947 दर्ज की गई थी, जिसका आधार स्पष्ट नहीं है; कि बाद में 1986 में उन्होंने अपनी माइनिंग सरदारशिप को क्लियर कर दिया और उन्हें माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट दिया गया, जिसमें उनकी जन्म तिथि 6 फरवरी 1950 दर्ज की गई थी, जैसा कि उनके स्कूल छोड़ने के प्रमाणपत्र में था; कि बाद में 1987 में, अपने सर्विस रिकॉर्ड में गलत जन्म तिथि और अन्य विवरणों को नोटिस करने पर, प्रत्यर्थीने तुरंत अपनी जन्म तिथि को 6 फरवरी, 1950 के रूप में सुधारने और अपने सर्विस रिकॉर्ड

में अन्य मामूली सुधारों के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया। अपने वरिष्ठों से पूछताछ पर इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलने पर, उन्हें यह धारणा दी गई कि सेवा रिकॉर्ड में आवश्यक सुधार किए गए थे और प्रत्यर्थीगलत जन्म तिथि 15 फरवरी, 1947 के आधार पर 2006 में अपना सेवानिवृत्ति आदेश प्राप्त करके आश्चर्यचकित था|

**6.** इन परिस्थितियों में, प्रत्यर्थी ने सबसे पहले यह तर्क दिया है कि यह मामला नहीं है कि प्रत्यर्थी ने सेवा के अंत में जन्म तिथि पर विवाद किया था, इसके बजाय उसने वर्ष 1987 में उसी तरह से विवाद किया था, यह नियोक्ता है जिसने यह धारणा पैदा करके अंतिम छोर पर विवाद किया था कि जन्म तिथि के सुधार के लिए प्रत्यर्थी का दावा स्वीकार किया गया था, जब वास्तव में, यह नहीं था और यहां तक कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने भी सहमति व्यक्त की है कि अंतिम छोर पर सुधार की मांग नहीं की गई थी। "" "दूसरा, यह तर्क दिया गया था कि प्रत्यर्थीने 6 फरवरी, 1950 के रूप में अपनी जन्म तिथि में सुधार के लिए दो दस्तावेजों पर भरोसा किया है, अर्थात् वैधानिक खनन सरदार प्रमाणपत्र और स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र।" "" यह तर्क दिया गया है कि कार्यान्वयन निर्देश संख्या 76 के भाग (ख) में निहित नीति के आलोक में खंड (i) (क) के अनुसार अपीलार्थी ने स्कूल छोड़ने के प्रमाणपत्र को स्वीकार कर लिया, हालांकि, इस तर्क को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि स्कूल रिकॉर्ड नौकरी में शामिल होने से पहले बनाए गए थे और बाद की तारीख में जारी की गई प्रति से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्रमाण

पत्र जारी करने की तारीख उस तारीख पर आधारित होती है जब प्रासंगिक रिकॉर्ड बनाया गया था। इसके अलावा, यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अपीलीय अदालत ने अपीलार्थी को स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र की वास्तविकता को सत्यापित करने के लिए समय दिया था और एक पूरक हलफनामे के माध्यम से जवाब में, अपीलार्थियों ने स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र को वास्तविक स्वीकार किया है, इस प्रकार प्रत्यर्थीद्वारा तर्क दिया गया है कि चूंकि स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र वास्तविक पाया गया था, इसलिए इसमें कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। चौथा, प्रत्यर्थी द्वारा यह तर्क दिया गया है कि सुधार के लिए उसके दावे पर खनन सरदार प्रमाणपत्र के आधार पर विचार नहीं किया गया था, जैसा कि दावा किया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है और उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसका उल्लेख कार्यान्वयन निर्देश संख्या 76 के भाग बी में खंड (i) (बी) में जन्म तिथि के सुधार के आधार के रूप में भी किया गया है।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी ने कोई कारण नहीं बताया कि उनके द्वारा खनन सरदार प्रमाणपत्र को क्यों अस्वीकार कर दिया गया था।। अंत में, प्रत्यर्थी ने प्रस्तुत किया है कि उसे समय से पहले सेवानिवृत्त किया गया था और उच्च न्यायालय के अनुकूल आदेशों के बावजूद काम करने की अनुमति नहीं दी गई थी; इसके अलावा, प्रत्यर्थी ने अवमानना याचिका दायर की थी, लेकिन उच्च न्यायालयों के समक्ष मामले के लंबित होने के बहाने याचिकाकर्ताओं द्वारा काम करने की अनुमति नहीं दी गई थी। प्रत्यर्थी का यह भी मामला है कि वह उस अवधि के दौरान कहीं और लाभकारी रूप से कार्यरत नहीं था|

**7.** इस बिंदु पर यह ध्यान देना उचित है कि मौखिक कार्यवाही के दौरान, इस अदालत ने 4 जुलाई, 2013 के आदेश के माध्यम से अपीलकर्ताओं को निम्नलिखित निर्देश दिएः

> *चार सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करें ताकि याचिकाकर्ताओं के वकील को फॉर्म 'बी' रजिस्टर की मूल और फोटोकॉपी भी प्रस्तुत करने में सक्षम बनाया जा सके, जहां यह आरोप लगाया गया है कि प्रत्यर्थीने जन्म तिथि पर अपने हस्ताक्षर किए थे जो 15.02.1947 के रूप में दर्ज किया गया था।*

तथापि, जैसा कि हमने पाया और प्रत्यर्थी ने 1973 में तैयार किए गए मूल प्रपत्र 'ख' को फाइल करने के बजाय, प्रत्यर्थी के विस्फोटक वाहक के पदनाम के साथ शामिल होने के समय (जिस पर प्रत्यर्थी के हस्ताक्षर होने का दावा किया गया था) 27 जनवरी, 1987 के कथित प्रपत्र 'ख' की एक फोटोकॉपी दाखिल की, जिसमें प्रत्यर्थी का पदनाम खनन सरदार का दिखाया गया था|

प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि रिकॉर्ड के आवश्यक सुधार के लिए उसी की फोटोकॉपी सौंपते समय 27 जनवरी, 1987 को कथित फॉर्म पर उनके हस्ताक्षर किए गए थे।

**8.** उपरोक्त के आधार पर, हम पाते हैं कि दिए गए तथ्यों के समूह के भीतर विवाद उस तरीके के बारे में है जिसमें जन्म तिथि निर्धारित की जानी चाहिए; क्या माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट और स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट के रिकॉर्ड के सेट पर निर्भरता रखी जानी चाहिए, जिसमें जन्म तिथि 6 फरवरी 1950 बताई गई है, या निर्भरता फॉर्म बी रजिस्टर के अर्क पर रखी जानी चाहिए जिसमें जन्म तिथि 15 फरवरी 1947 बताई गई है| उपरोक्त के आधार पर जो स्थिति सामने आती है वह यह है कि 1973 में सेवा में शामिल होने के बाद

जब फॉर्म 'बी' रजिस्टर भरा गया था और जब 1983 में एक बार फिर भरा गया था जब प्रत्यर्थीका स्थानांतरण किया गया था, तो स्थायी पता पिता के नाम और नौकरी में शामिल होने की तारीख के संबंध में कुछ विसंगतियां थीं| 1987 में, जब अपीलार्थी ने सेवा अभिलेखों के सत्यापन के लिए सभी कर्मचारियों का विवरण उपलब्ध कराया, तो प्रत्यर्थी ने अपने नौकरी में शामिल होने की तारीख, पिता का नाम, स्थायी पता और जन्म तिथि सम्बंधित गलत विवरणों के बारे में विवाद उठाया। जाहिर है, जन्म तिथि के अलावा उपर्युक्त सुधार किए गए थे। इस प्रकार, यह विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा स्पष्ट और सही ढंग से निर्धारित किया जाता है कि विवाद सेवा के अंतिम चरण में या सेवानिवृत्ति की पूर्व संध्या पर नहीं उठाया गया था, बल्कि इसे 1987 में जल्द से जल्द संभव अवसर पर उठाया गया था जब प्रत्यर्थीको विसंगति का पता चला था। चूंकि विवाद कब उठाया गया था, इस तथ्य का निपटारा किया जा चुका है, इसलिए अभी जन्म तिथि का मुद्दा निर्धारित किया जाना बाकी है| ।

**9.** एक समय की अवधि में सेवा कानून के कोष में, जन्म तिथि विवादों के प्रति एक निश्चित दृष्टिकोण इस न्यायालय के निर्णयों के आलोक में उभरा है क्योंकि एक कर्मचारी की जन्म तिथि में परिवर्तन से उत्पन्न प्रभाव पत्थर के एक टुकड़े को पानी में गिराए जाने पर उत्पन्न दूरगामी लहरों के समान है। इस न्यायालय ने इसे संक्षेप में में निर्धारित किया है *सचिव और आयुक्त, गृह विभाग बनाम . आर. किरुबाकरन* (ऊपर), जो नीचे दिया गया हैः-

*" 7. " जन्म तिथि में सुधार के लिए आवेदन पर केवल संबंधित लोक सेवक को ध्यान में रखते हुए न्यायाधिकरण या उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जाना चाहिए। यह इंगित करने की आवश्यकता नहीं है कि जनता की जन्म तिथि में सुधार के लिए ऐसा कोई निर्देश संबंधित सेवक की एक श्रृंखला प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि अन्य लोग वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, इस प्रक्रिया में उनके संबंधित पदोन्नति के लिए उनके नीचे प्रभावित होते हैं। कुछ को अपूरणीय क्षति होने की संभावना है, जैसे कि, जन्म तिथि में सुधार के कारण, संबंधित अधिकारी, कार्यालय में जारी है, कुछ मामलों में वर्षों के लिए, जिस समय के भीतर कई अधिकारी जो वरिष्ठता में उनसे नीचे हैं, अपनी पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अपने प्रमोशन हमेशा के लिए खो सकते हैं। ऐसे मामले अज्ञात नहीं हैं जब कोई व्यक्ति अपने तत्काल वरिष्ठ की सेवानिवृत्ति की तारीख को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति स्वीकार करता है। हमारे अनुसार, यह एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसे किसी लोक सेवक की जन्म तिथि में सुधार के संबंध में शिकायत की जांच करते समय अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस तरह, जब तक कोई स्पष्ट मामला, उन तथ्यों के आधार पर, जिन्हें प्रकृति में निर्णायक माना जा सकता है, प्रत्यर्थीद्वारा नहीं बनाया जाता है, अदालत या न्यायाधिकरण को उन तथ्यों के आधार पर कोई निर्देश जारी नहीं करना चाहिए, जो इस तरह के दावे को केवल प्रशंसनीय बनाती हैं। ऐसा कोई निर्देश जारी किए जाने से पहले, न्यायालय या अधिकरण को पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति के साथ वास्तविक अन्याय हुआ है और जन्म तिथि में सुधार के लिए उसका दावा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार और किसी नियम या आदेश द्वारा निर्धारित समय के भीतर किया गया है। यदि कोई नियम या आदेश नहीं बनाया गया है, जिसमें उस अवधि को निर्धारित किया गया है जिसके भीतर ऐसा आवेदन दायर किया जाना है, तो ऐसा आवेदन उस समय के भीतर दायर किया जाना चाहिए, जिसे उचित माना जा सकता है। आवेदक को इस तरह के दावे के समर्थन में सबूत पेश करना होगा, जो उसकी जन्म तिथि से संबंधित अकाट्य सबूत के बराबर हो सकता है| जब भी ऐसा कोई सवाल उठता है, तो अपनी सर्विस बुक में अपनी जन्म तिथि की गलत रिकॉर्डिंग साबित करने की ज़िम्मेदारी आवेदक पर होती है| कई मामलों में ऐसे लोक सेवकों की ओर से यह रणनीति का एक हिस्सा है कि वे अपनी सेवानिवृत्ति की पूर्व संध्या पर अदालत या न्यायाधिकरण से संपर्क करें, सेवा पुस्तकों में उनकी जन्म तिथि के संबंध में प्रविष्टियों की शुद्धता पर सवाल उठाएं। इस प्रक्रिया से, यह इस न्यायालय के ध्यान में आया है कि कई मामलों में, भले ही अंततः उनके आवेदन हों*

*बर्खास्त, अंतरिम आदेशों के आधार पर, वे सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद महीनों तक जारी रहते हैं। अदालत या न्यायाधिकरण को चाहिए, इसलिए, सेवा में बने रहने के लिए अंतरिम राहत देने में धीमी रहें, जब तक कि प्रथम दृष्टया निर्दोष चरित्र का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जाता है क्योंकि यदि लोक सेवक सफल होता है, उसे हमेशा मुआवजा दिया जा सकता है, लेकिन अगर वह असफल हो जाता है, उन्होंने विस्तारित सेवा का अनुचित लाभ उठाया होगा और केवल अपने तत्काल जूनियर के साथ अन्याय किया होगा।*

इसी दृष्टिकोण का पालन इस न्यायालय द्वारा जन्म तिथि के विवादों पर निर्णय लेते समय किया गया था, भले ही राहत कर्मचारी या नियोक्ता के पक्ष में हो। (देखें: *पंजाब राज्य बनाम एससी चड्ढा* [3] " , *उत्तर प्रदेश का राज्य और एएनआर। वी. शिव नारायण उपाध्याय* [4] " , *गुजरात राज्य और अन्य बनाम वली मोहम्मद दोसाभाई सिंधी* [5] " , *महाराष्ट्र राज्य और उत्तर प्रदेश बनाम गोरकनाथ सीताराम कांबले* [6] " )

ऐसे विवादों के संबंध में अदालतों द्वारा अपनाई जाने वाली एक अन्य प्रथा यह है कि किसी कर्मचारी की जन्म तिथि का निर्धारण निर्धारित लागू नियमों या संगठन में मौजूद ढांचे के अनुसार किया जाता है। यहां तक कि इस न्यायालय ने भी अनुच्छेद 136 के तहत प्रदत्त असाधारण शक्तियों के बावजूद लागू नियमों के अनुसार जन्म तिथि का फैसला किया है और शायद ही कभी न्यायालय ने जन्म तिथि निर्धारित की है क्योंकि यह उचित फोरम द्वारा निर्धारित किया जाने वाला तथ्य का प्रश्न है|

" [3] " " " (2004) 3 एससीसी 394
" [4] " " " (2005) 6 एससीसी 49
" [5] " " " (2006) 6 एससीसी 537

" [6] " " (2010) 14 एससीसी 423

(देखें: *महाराष्ट्र राज्य और उत्तर प्रदेश बनाम गोरखनाथ सीताराम कांबले और अन्य* ." [7] " *पंजीयक जनरल, मद्रास उच्च न्यायालय बनाम एम. माणिकम एंड ओआरएस."* [8] *आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय बनाम उत्तर प्रदेश संन्यासी राव* [9] " )
जैसा कि पहले कहा गया है, इस न्यायालय को यह तय करने की आवश्यकता है कि जन्म तिथि का निर्धारण किस तरीके से किया जाना है। यह अपीलार्थी का मामला है कि जैसा कि प्रत्यर्थी ने अपने करियर के अंत में विवाद उठाया था और चूंकि फॉर्म बी रजिस्टर होने के कारण रिकॉर्ड का एक सेट मौजूद है जो एक वैधानिक दस्तावेज है जिसमें जन्म तिथि को स्वयं उत्तरदाता द्वारा दो बार सत्यापित किया गया है, अन्य गैर-वैधानिक दस्तावेजों को प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए और उच्च न्यायालय के आदेशों को दरकिनार कर दिया जाना चाहिए। अपीलार्थी का यह दावा वर्तमान मामले में उचित नहीं है। जैसा कि निर्धारित किया गया है, विवाद कैरियर के अंतिम चरण में नहीं उठाया गया था; इसके विपरीत, यह 1987 में उनकी सेवानिवृत्ति से लगभग दो दशक पहले जब उन्हें पहली बार विसंगति का पता चला था तब उठाया गया था |

यह माना गया है *मोहम्मद यूनुस खान बनाम यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड"* [10] , वह, *"एक कर्मचारी यह जानने के बाद कि नियोक्ता द्वारा गलती की गई है, कानूनी रूप से अनुमत कार्रवाई कर सकता है"।* इस प्रकार, प्रत्यर्थी के मामले को अनुचित देरी के कारण प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। मान लीजिए कि अपीलार्थी नियोक्ता के रूप में अपने स्वयं के विनियमों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता III में निहित कार्यान्वयन निर्देश सं. 76 ने अपने सभी कर्मचारियों को सेवा रिकॉर्ड में विसंगतियों की पहचान करने और उन्हें सुधारने का मौका दिया । अपीलकर्ताओं की इस पहल ने स्पष्ट रूप से सेवा रिकॉर्ड में त्रुटियों के अस्तित्व का संकेत दिया, जिसके बारे में अपीलकर्ता जानते थे और इसे ठीक करने के लिए कदम उठा रहे थे। इस पृष्ठभूमि में, अपीलार्थी का रुख कि फॉर्म बी रजिस्टर में रिकॉर्ड पर भरोसा किया जाना चाहिए, अच्छा नहीं है क्योंकि अपीलार्थी द्वारा यह स्वीकार किया

गया है कि उसमें त्रुटियां मौजूद थीं। यहां तक कि नामांकित प्रपत्र का अध्ययन भी जन्म तिथि और नौकरी में शामिल होने की तिथि के बारे में अस्पष्टता को दर्शाता है। इन्ही विसंगतियों के कारण  अपीलकर्ताओं ने अपने सभी कर्मचारियों को इसे सुधारने का मौका दिया। ऐसी परिस्थितियों में, अपीलार्थी अपने कृत्यों द्वारा बाध्य हैं और प्रत्यर्थी के दावों को नकारने का उनका प्रयास गलत है। इस मामले में प्रत्यर्थी ने उपलब्ध प्रक्रिया का विधिवत पालन किया और तकनीकी आधार पर प्रत्यर्थी के दावे को अस्वीकार करने का अपीलार्थी का प्रयास गलत है। इसलिए, हम महसूस करते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह सही माना हैः

*" **11** . याचिकाकर्ता को, सभी कर्मचारियों की तरह, उनकी जन्म तिथि सहित उनके सेवा रिकॉर्ड में निहित प्रविष्टियों में सुधार की मांग का लाभ देने के बाद, याचिकाकर्ता के दावे को केवल इसलिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि उसने नौकरी में शामिल होने के समय फॉर्म बी रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए थे और उसमें जन्म तिथि की प्रविष्टि दर्ज थी।*

**I.** वर्तमान मामले में अपीलार्थी को किसी मौजूदा कर्मचारी की जन्म तिथि निर्धारित करने के लिए कार्यान्वयन निर्देश संख्या 76 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था।। जिनके प्रावधान इस प्रकार हैं-

" *(बी)"* **मौजूदा एम्प्लॉई के संबंध में जन्म तिथि के निर्धारण की समीक्षा।**

" *(आई) (ए) "* मौजूदा एम्प्लॉई के मामले में मैट्रिक सर्टिफिकेट ऑफ़ (एसआईसी: या)  बोर्ड के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों द्वारा जारी हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट या शिक्षा बोर्ड और/या लोक निर्देश विभाग द्वारा जारी मिडिल

पास सर्टिफिकेट और उपरोक्त निकायों द्वारा जारी किए गए प्रवेश पत्रों को सही माना जाना चाहिए, बशर्ते कि वे रोजगार की तारीख से पहले उक्त विश्वविद्यालयों/बोर्ड संस्थानों द्वारा जारी किए गए हों।

" *(आई) (बी)* " इसी तरह, माइनिंग सरदारशिप, वाइंडिंग इंजन या इसी तरह के अन्य वैधानिक प्रमाण पत्र जहां प्रबंधक को जन्म तिथि प्रमाणित करनी थी, को प्रामाणिक माना जाएगा।

प्रदान किया गया है कि जहां दोनों दस्तावेजों का उल्लेख किया गया है *(आई) (ए)* " और *(आई) (बी)* " ऊपर उपलब्ध हैं, जन्म तिथि दर्ज की गई है *(आई) (ए)* " प्रामाणिक माना जाएगा

*(ii)* जहां भी रिकॉर्ड में कोई भिन्नता नहीं है, ऐसे मामलों को तब तक फिर से नहीं खोला जाएगा जब तक कि प्रबंधन के ध्यान में एक बहुत ही स्पष्ट और स्पष्ट गलत प्रविष्टि नहीं लाई जाती है। प्रबंधन मामले के गुण-दोष से संतुष्ट होने के बाद निर्धारण समिति/मेडिकल बोर्ड के माध्यम से सुधार के लिए उचित कार्रवाई करेगा।

(C) उपरोक्त के लिए आयु निर्धारण समिति/मेडिकल बोर्ड का गठन प्रबंधन द्वारा किया जाएगा। उन कर्मचारियों के मामले में जिनकी जन्म तिथि में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित नहीं की जा सकती है *(बी) (i) (ए)* " या *(बी) (i) (बी)* " ऊपर, कंपनी के रिकॉर्ड में दर्ज जन्म तिथि, अर्थात्, फॉर्म बी रजिस्टर, सीएमपी रिकॉर्ड और पहचान पत्र (अनटैम्पर्ड) को अंतिम माना जाएगा। बशर्ते कि ऊपर बताए गए रिकॉर्ड में दर्ज आयु में कोई भिन्नता हो, तो मामला आयु निर्धारण समिति/मेडिकल बोर्ड को भेजा जाएगा आयु के निर्धारण के लिए प्रबंधन द्वारा गठित

*(D)* उम्र का दृढ़ संकल्प: ऊपर निर्दिष्ट आयु निर्धारण समिति/मेडिकल बोर्ड द्वारा कोलियरी प्रबंधन के पास उपलब्ध उनके साक्ष्य पर विचार किया जा सकता है; और/या

(E) आयु निर्धारण के लिए गठित मेडिकल बोर्ड को प्रबंधन करने की आवश्यकता होगी ( *एसआईसी* आकलन) चिकित्सा न्यायशास्त्र और चिकित्सा बोर्ड की आवश्यकता के अनुसार आयु जहां तक संभव हो, मूल्यांकन की गई सटीक आयु का संकेत देगी, न कि लगभग।

एक अन्य मामले में, होना *जी. एम. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बनाम शिब कुमार दुशाद* (ऊपर) जहां भारत कोकिंग कोल के एक कर्मचारी की जन्म तिथि विवाद में थी और

निर्देशों का वही सेट लागू था, कार्यान्वयन निर्देश का उल्लेख करते हुए इस अदालत ने कहा किः

*" **20.** " ऊपर निर्दिष्ट निर्देशों के प्रावधानों से, यह स्पष्ट है कि किसी मौजूदा कर्मचारी की जन्म तिथि को लेकर विवाद के मामले में, जिसके पास न तो मैट्रिक सर्टिफिकेट/सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है और न ही कोई वैधानिक सर्टिफिकेट है, जिसमें मैनेजर ने जन्म तिथि के संबंध में प्रविष्टि को प्रामाणिक होने के लिए प्रमाणित किया है, एम्प्लॉयर को इस मामले को मेडिकल बोर्ड को भेजना है।*

21. हम जन्मतिथि के विवादों की संवेदनशील प्रकृति को उचित सम्मान देते हैं और आर. किरुबाकरन मामले में निर्धारित दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं (supra)। हालांकि, इसे रोकने के उद्देश्य से जन्म तिथि में बदलाव के कारण होने वाली असुविधाओं के कारण, एक अन्यायपूर्ण कर्मचारी को उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, खासकर जब उसने निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया हो और इन-हाउस तंत्र का सहारा लेकर मुकदमेबाजी से बचने का प्रयास किया हो। सार्वजनिक निगमों/विभागों को अपने स्वयं के कर्तव्य की चूक से लाभ नहीं होना चाहिए। वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता-कंपनी कार्यान्वयन निर्देश में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने में विफल रही। यह अपीलार्थी की चूक है न कि प्रत्यर्थी की निष्क्रियता जिसके कारण अदालतों में इस तरह के विलंबित चरण में विवाद उठाया गया। ऐसे निगमों का रवैया जिसमें जन्म तिथि में सुधार से बचना है, मुकदमेबाजी अनावश्यक रूप से लंबी होती है क्योंकि उनके पास कई संसाधन होते हैं, यह बड़े पैमाने पर समाज के प्रति समानता और कर्तव्य के खिलाफ जाता है।

22."" "जैसा कि हमने नोट किया है, 1987 में उत्तरदाता को नॉमिनेशन फॉर्म से अपने सर्विस रिकॉर्ड में अपनी जन्म तिथि की गलत रिकॉर्डिंग के बारे में पता चलने पर सुधार की मांग की।" "" इसलिए, उनकी सेवा के अंतिम चरण में इस तरह के सुधार की मांग नहीं की गई थी। हमने आगे पाया है कि उच्च न्यायालय ने 6 सितंबर, 2010 को उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता कंपनी के कानूनी निरीक्षक श्री दिलीप कुमार मिश्रा द्वारा दायर एक पूरक हलफनामे के आधार पर स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र की वास्तविकता को विधिवत सत्यापित किया। उक्त सप्लीमेंट्री एफिडेविट में यह स्वीकार किया गया है कि स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट वेरीफाई किया गया है और यह वास्तविक पाया गया है। हमने आगे देखा है कि कार्यान्वयन निर्देश No.76 खंड (आई) (ए) स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र में बताई गई जन्म तिथि को सही मानते हुए जन्म तिथि में सुधार की अनुमति देता है बशर्ते कि ऐसे प्रमाण पत्र शैक्षणिक संस्थान द्वारा रोजगार की तारीख से पहले जारी किए गए हों। जारी किए गए शब्दों की व्याख्या करने के प्रश्न की सही व्याख्या की गई थी, हमारी राय में, उच्च न्यायालय द्वारा, जिसने रोजगार की अवधि बढ़ाने के उद्देश्य से प्रमाणपत्रों के दुरुपयोग से सुरक्षा के उद्देश्य से उक्त शब्दों की व्याख्या की उच्च न्यायालय ने सही व्याख्या की और इसका मतलब यह था कि ये शब्द वहां लागू नहीं होंगे जहां जन्म तिथि वाले स्कूल रिकॉर्ड रोजगार शुरू होने से बहुत पहले उपलब्ध थे। प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख वास्तव में उस स्कूल में प्रासंगिक रिकॉर्ड के साथ उस तारीख को

संदर्भित करने का इरादा रखती है जिसके आधार पर प्रमाणपत्र जारी किया गया है|

एक स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र आमतौर पर छात्र द्वारा स्कूल छोड़ने के समय जारी किया जाता है, बाद में इसकी एक प्रति भी प्राप्त की जा सकती है जहां एक छात्र अपने उक्त स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र को भूला देता है और इसकी एक नई प्रति के लिए आवेदन करता है। नई कॉपी जारी करने से उस प्रासंगिक रिकॉर्ड को बदला नहीं जा सकता है जो स्कूल के रिकॉर्ड में छात्र के प्रवेश की तारीख और जन्म तिथि से स्कूल के रिकॉर्ड में प्रचलित है, जिसे स्कूल के रिकॉर्ड में विधिवत दर्ज किया गया है।

23. इसलिए, उच्च न्यायालय के आदेश में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। हम उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क का समर्थन करते हैं और इसकी पुष्टि करते हैं।

24. इन परिस्थितियों में, हमें अपील में कोई योग्यता नहीं मिलती है. तदनुसार, यह अपील खारिज कर दी जाती है।

. " जे.
(ज्ञान सुधा मिश्रा)

नई दिल्ली;
25 मार्च, 2014
(पिनाकी चंद्र घोष)

**<u>यह अनुवाद पीयूष आनन्द, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया है।</u>**